*423. [The questioner (Shri Lalit Kishore Chaturvedi) was absent. For answer *vide* page 37 infra.]

Assistance sought by Karnataka

*424. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Ministry of SMALL SCALE INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government of Karnataka has sought assistance for upgradation of existing Tool Room and Training Centre at Hassan and for improvement of productivity and quality of Kolhapuri footwear cluster at Athani, Belgaum district, under the Small Industry Cluster Development Programme; and

(b) if so, the details in this regard and the Central Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF SMALL SCALE INDUSTRIES (SHRI MAHAVIR PRASAD): (a) and (b) A statement is placed on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) The State Government of Karnataka had submitted a proposal for financial assistance on 29.11.2004 under the Mini Tool Room Scheme to upgrade the existing Tool Room and Training Centre at Hassan and another proposal on 22.2.2005 under the Small Industry Cluster Development Programme (SICDP) to establish a Common Facility Centre for Leather Footwear Cluster at Athani in Belgaum District.

Both the proposals were examined in detail. It was found that the first proposal was neither in the prescribed format nor was in accordance with the guidelines of the Scheme. The second proposal was found lacking in some essential details. The State Government has been requested to resubmit the proposals.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, there is a Tool Room and a Training Centre at Hassan. For upgradation of this Centre a proposal has been sent to the Government of India. But, Sir, the Government of India has sought some clarification. Revised projection indicating justification for establishing of GTCC was submitted in the month of May. I would like to know whether the hon. Minister is going to clear it as early as possible.

श्री महावीर प्रसाद: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, हासन के संदर्भ में पूछा है। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है, चूंकि यह प्रश्न राज्य सरकार के प्रस्ताव से संबंधित है, माननीय सदस्य महोदय काफी सीनियर सदस्य हैं। मैं इनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि...

श्री सभापति: आप इनके संज्ञान में मत लाइये।.आप इनके प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि आप उस पर विचार कर रहे हैं या नहीं।

श्री महावीर प्रसाद: सभापति महोदय, प्रस्ताव पर विचार करने के बारे में, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि यह प्रस्ताव अभी विचार करने की स्थिति में नहीं है। इसी संदर्भ में, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा.. ।

श्री सभापति: नहीं है, तो मना कर दीजिए कि नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद: सभापति महोदय, ठीक है। आपकी आज्ञा से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि उस प्रस्ताव में बहुत सी कमियां हैं। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि राज्य सरकार की तरफ से उन कमियों को दूर कराकर प्रस्ताव को भेजें, मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री सभापति: ठीक है।

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, it is unfortunate that the hon. Minister is not aware of the fact that justification for revised project was sent in the month of May. Whatever it may be, now it is in the possession of the Government of India. Now, I come to my second supplementary. I would like to say that in order to improve productivity and also the quality of the products manufactured by the leather artisan at Athani Taluk in Belgaum district, Sir, a proposal has been prepared under the Small Industry Cluster Development Programme for seeking financial assistance. That proposal is also pending. Now it is in connection with the same question that I have put. I would like to know whether the hon. Minister is going to clear that also.

श्री महावीर प्रसाद: सभापति महोदय, मैंने इनके पहले प्रश्न के उत्तर में बताया है कि संबंधित राज्य सरकार से बेलगांव जिले में अठानी स्थित कोल्हापुरी फुटवेयर क्लस्टर के संदर्भ में भी प्रस्ताव आया है। मैं जानता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन फुटवेयर क्लस्टर के संदर्भ में यदि आपकी आज्ञा हो, तो मैं बताना चाहता हूं.।

श्री सभापति: आप इनको बता दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद: सभापति महोदय, मैं इनको बताना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव में जो कमियां हैं, उन कमियों को पूरा कराकर राज्य सरकार की तरफ से दोबारा भेज दें, तो मैं उस पर विचार करूंगा।

लंबित पड़ी सिंचाई परियोजनाएं

*425. **श्री मोती लाल वोरा:** †
श्री जनार्दन द्विवेदी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने के लिए लंबित पड़ी सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) लंबित सिंचाई परियोजनाओं की समस्याओं को सुलझाने, बंजर भूमि तथा सूखा प्रभावित क्षेत्रों का विकास करने के लिए दसवीं योजना की शेष अवधि तथा ग्यारहवीं योजनावधि के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि की जरूरत है;

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में बड़ी परियोजनाओं के लिए राज्यों ने योगदान करने से मना कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का उपरोक्त परियोजनाओं के लिए निधियों का किस प्रकार प्रबंध करने और प्रावधान करने का विचार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) 01 अप्रैल, 2004 की स्थिति के अनुसार लगभग 91114 करोड़ रु० अतिशेष लागत की 169 बड़ी और 219 मंझोली सिंचाई परियोजनाएं दसवीं योजना में भी लम्बित हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। (नीचे देखिए) दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन ने जल क्षेत्रक में सुधारों के साथ 100 केन्द्रीय वित्त पोषण सहित कुछ बड़ी परियोजनाएं राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में शुरू करने का सुझाव दिया है।

सिंचाई परियोजनाओं से सूखा प्रवण क्षेत्रों को होने वाले लाभ के अतिरिक्त,सूखा-प्रवण क्षेत्रों, मरूभूमि क्षेत्रों और बंजरभूमि के लिए भी केन्द्र प्रायोजित स्कीमें क्रियान्वित की जा रही है।

---

† सभा में यह प्रश्न श्री मोती लाल वोरा द्वारा पूछा गया।